Ram Kumar v. Chelu Ram (D. V. Sehgal, J.)

डी.वी. सहगल, जे.के समक्ष

राम कुमार,-अपीलकर्ता।

बनाम

चेलू राम, प्रतिवादी.

1986 के आदेश क्रमांक 7 से द्वितीय अपील

14 मई, 1986.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश VI नियम 9 और आदेश VII नियम 11 और 14 - जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है उसकी एक प्रति के साथ वाद दायर किया गया - कहा गया वाद पत्र कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करने के कारण समयपूर्व होने के कारण खारिज कर दिया गया - दिए गए कथन लिखित कथन में - क्या अस्वीकृति का आदेश पारित करने से पहले विचार किया जा सकता है - वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज - क्या ऐसा आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है - वाद पत्र को खारिज करने का आदेश - क्या वैध है।

माना गया कि यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई वादपत्र कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है या नहीं, न्यायालय को वादपत्र में दिए गए कथनों पर गौर करना होगा और उन्हें फिलहाल सही मानना होगा। यह लिखित बयान या किसी अन्य में दिए गए कथनों पर निर्भर नहीं हो सकता

इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी में दिए गए कथन सही नहीं हैं, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 11 के तहत इसे खारिज कर देता है। 1908. हालाँकि, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश VI, संहिता के नियम 9 में प्रावधान है कि जहां भी किसी दस्तावेज़ की सामग्री महत्वपूर्ण है, यह किसी भी दलील में उसके प्रभाव को पूरी तरह से बताए बिना संक्षेप में बताने के लिए पर्याप्त होगा। एक ही समय पर संहिता के आदेश VII नियम 14 में यह प्रावधान है कि जहां

वादी अपने कब्जे या शक्ति में किसी दस्तावेज़ पर मुकदमा करता है, तो वह वाद प्रस्तुत होने पर इसे अदालत में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज़ या उसकी एक प्रति दाखिल करने के लिए देगा। संहिता के इन प्रावधानों का पूरा उद्देश्य यह है कि दलीलों को प्रचुरता से मुक्त होना चाहिए, लेकिन मुकदमे का आधार बनने वाला दस्तावेज वादपत्र के साथ उपलब्ध हो ताकि उसमें निहित कथनों की सराहना की जा सके। इस प्रकार वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ कमोबेश वाद-पत्र का एक भाग बन जाता है। संहिता के आदेश VII, नियम 11 के तहत एक वादपत्र को खारिज करने के लिए न्यायालय को प्रारंभिक चरण में ही वादपत्र की सामग्री का अध्ययन करना होगा और किसी भी बचाव की सहायता के बिना वादपत्र के आधार पर अपना दृष्टिकोण बनाना होगा, चाहे वह इसका खुलासा करता हो। कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ या नहीं और वादी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज़ और वादी के साथ आने वाले दस्तावेज़ पर भी यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था या नहीं। ऐसे में अदालत का वाद पत्र खारिज करने का आदेश पूरी तरह वैध था।

(पैरा 4, 5 और 9)

श्री के.सी. डांग, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के न्यायालय के आदेश, 3 दिसंबर, 1985 से दूसरी अपील में श्री इंद्रजीत मेहता, एचसीएस उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, पानीपत की 3 सितंबर, 1985 को पलट दिया गया और मामले को कानून के अनुसार निपटान के लिए श्री इंद्रजीत मेहता, विद्वान उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, पानीपत की अदालत में भेज दिया गया और पक्षों को 21 दिसंबर 1985 को संबंधित अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सी. बी. गोयल।

प्रतिवादी की ओर से वकील ओ. पी. गोयल।

निर्णय

सी.वी. सहगल, जे.—

(1) राम कुमार प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने 20 अगस्त, 1953 को रुपये के प्रतिफल के लिए वादी-प्रतिवादी के पास एक ढाई मंजिला पक्की हवेली गिरवी रख दी। 1,000/-वादी ने 25 जनवरी 1985 को एक मुकदमा दायर किया जिसमें 20 अगस्त 1953 के बंधक विलेख का संदर्भ दिया गया था और यह विवादित नहीं है।

बशर्ते कि इसकी एक प्रति वादपत्र के साथ भी संलग्न की गई हो। हालाँकि, इसमें कहा गया था कि प्रतिवादी - बंधककर्ता ने 30 वर्षों के भीतर संपत्ति को भुनाया नहीं था और परिणामस्वरूप वादी समय के साथ इसका मालिक बन गया था। मुकदमे में इस आशय की घोषणा के लिए डिक्री की प्रार्थना की थी। प्रतिवादी ने एक लिखित बयान दायर करके मुकदमे का विरोध किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह आरोप लगाया था कि वादी द्वारा मुकदमा शुरू करने से एक दिन पहले, उसने बंधक के मोचन के लिए एक मुकदमा दायर किया था जो श्री पी. एल. खंडूजा, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, पानीपत अदालत में लंबित था। यह भी तर्क दिया गया कि उन्हें बंधक की तारीख से 5 साल के भीतर, बंधक राशि का भुगतान करके, यानी 20 अगस्त, 1958 तक संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार था। इसलिए, 30 साल की निर्धारित अवधि की सीमा तय की गई थी। उनके द्वारा मोचन के लिए मुकदमा दायर करना 20 अगस्त, 1958 को शुरू होना था, जो समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए, मुकदमा समय से पहले था और इसमें कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था।

(2) पक्षों की दलीलों पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया:

"क्या वादी' कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा नहीं करता है? ओपीडी ।"

3 सितंबर, 1985 को अपने फैसले और डिक्री द्वारा, विद्वान उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, पानीपत ने निम्नानुसार कहा: -

"ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, कार्रवाई का कारण 20 अगस्त, 1988 के बाद वादी-बंधकदार के पक्ष में जमा होगा और वर्तमान मुकदमा दायर करने की तारीख, यानी, 25 जनवरी, 1985 को, कार्रवाई का कोई कारण पक्ष में जमा नहीं हुआ है वादी का और इसलिए मुकदमा खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री तैयार की जाएगी। फ़ाइल को रिकॉर्ड - रूम में भेजा जाए।"

(3) वादी-अपीलकर्ता ने एक अपील दायर की, जिसे विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल ने 3 दिसंबर, 1985 के फैसले के तहत अनुमति दे दी। विद्वान ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया और मामला बंद कर दिया गया।

(4) विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने कुछ प्राधिकारियों पर भरोसा करते हुए माना कि आदेश VII, नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'संहिता' कहा जाएगा) के तहत यदि कार्रवाई के कारण का खुलासा किया जाता है तो वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई वादपत्र कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है या नहीं, न्यायालय को केवल वादपत्र में दिए गए कथनों पर गौर करना होगा और उन्हें फिलहाल सही मानना होगा। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि वादी में दिए गए कथन सही नहीं हैं, लिखित बयान में दिए कथन या प्रस्तुत किए गए किसी अन्य साक्ष्य पर निर्भर नहीं हो सकता है और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है और उसे अस्वीकार कर देता है। संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के तहत मेरे विचार में, कानून की यह स्थिति अपराजेय है।

(5) हालाँकि, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जैसा कि संहिता के आदेश VI, नियम 9 में निर्धारित है, जहां भी किसी दस्तावेज़ की सामग्री महत्वपूर्ण है, यह उसके प्रभाव को बताने के लिए किसी भी दलील में पर्याप्त होगी। संपूर्ण या उसके किसी भाग को बताए बिना संक्षेप में, जब तक कि दस्तावेज़ या उसके किसी भाग के सटीक शब्द महत्वपूर्ण न हों। साथ ही, आदेश VII, नियम 14 में प्रावधान है कि "जहां एक वादी अपने कब्जे या शक्ति में किसी दस्तावेज़ पर मुकदमा करता है, वह वाद प्रस्तुत होने पर इसे अदालत में पेश करेगा और साथ ही उसे वितरित करेगा।" वादपत्र के साथ दाखिल किया जाने वाला दस्तावेज़ या उसकी एक प्रति। संहिता के इन प्रावधानों का संपूर्ण उद्देश्य यह है कि जहां दलीलें बहुतायत से मुक्त होनी चाहिए, वहीं दस्तावेज जो मुकदमे का आधार बनता है, वह वादपत्र के साथ उपलब्ध होना चाहिए ताकि वादपत्र में निहित कथनों की सराहना की जा सके। इस प्रकार दस्तावेज़ को इसके साथ संलग्न किया गया। वाद-विवाद कमोबेश इसका एक हिस्सा बन जाता है।"

(6) मेरे सामने इस बात पर विवाद नहीं हुआ है कि बंधक विलेख जो पार्टियों के बीच विवाद का विषय है, उसमें निम्नलिखित कथन शामिल हैं: -

> "इकरार हुआ कि कुल ज़रे - रेहान माई सुद बा शारा एक रूपया शंकर महावर अरसा पंच साल मैं अदा मुर्तहिं करके मकान मार-हुना फ़क कारवालुंगा"

(7) बंधक में निहित लगभग समान पाठ विचार के लिए आया, प्रिवी काउंसिल के समक्ष बख्तावर बेगम

(1) A.I.R. 1914 P.C. 36.

वि. हुसैनी खानम (1) में. उस मामले में गिरवीकर्ता ने 12 गांवों के संबंध में सशर्त बिक्री के माध्यम से एक बंधक निष्पादित किया। गिरवीदार द्वारा गिरवीकर्ता के साथ एक समसामयिक समझौता किया गया था कि बंधककर्ता 9 वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रतिफल की राशि के भुगतान पर संपत्ति वापस दावा कर सकता है। इस खंड की व्याख्या करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि ऋण 9 वर्षों की अवधि तक बकाया रहा और उसे भुनाने का अधिकार केवल उस अवधि की समाप्ति पर ही प्राप्त होता है। उपरोक्त अनुबंध पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या का विज्ञापन करते समय, प्रिवी काउंसिल के उनके आधिपत्य ने कहा:-

"आमतौर पर, और बंधककर्ता को उस अवधि के दौरान छुड़ाने का अधिकार देने वाली एक विशेष शर्त के अभाव में, जिसके लिए बंधक बनाया गया है, मोचन का अधिकार केवल निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर ही उत्पन्न हो सकता है। लेकिन पार्टियों को यह प्रावधान करने से रोकने के लिए कानून में कुछ भी नहीं है कि बंधककर्ता निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऋण का भुगतान कर सकता है और संपत्ति वापस ले सकता है। ऐसा प्रावधान आमतौर पर बंधककर्ता के लाभ के लिए होता है। वर्तमान मामले में, यदि मामला केवल कलेक्टर की कार्यवाही में दिए गए अनुबंध के निर्माण पर निर्भर होता, तो उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता था।

(8) इस संबंध में बख्तावर बेगम के मामले (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल द्वारा लिए गए कानून के उपरोक्त दृष्टिकोण को गंगा धर बनाम शंकर लाई और अन्य (2) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया है, और हाल ही में एस.पी.गोयल द्वारा जे. शंभु दयाल बनाम श्रीमती तारावंती और अन्य (3) में इसका पालन किया गया है। इसलिए, मेरा सुविचारित विचार है कि बंधक की मुक्ति के लिए अपीलकर्ता द्वारा मुकदमा दायर करने के लिए सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 61 के तहत सीमा का प्रारंभिक बिंदु 20 अगस्त, 1953 से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर शुरू होगा। इसलिए, उनके लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा 20 अगस्त, 1988 को समाप्त हो जाएगी। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस दृष्टिकोण के विरोध में कई अधिकारियों का हवाला दिया। हालाँकि, उन पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्हें पढ़ने पर मुझे पता चला है कि उनमें से किसी का भी मेरे सामने मौजूद प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है।

(9) निस्संदेह, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा अपने लिखित बयान में कही गई बातों पर विचार किया; तब

(1)A.I.R. 1914 P.C. 36.
(2)A.I.R. 1958- S.C. 770.
(3)A.I.R. 1985 Pb. & Hry. 21.

एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया और अंततः माना कि मुकदमे में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया। 'संहिता के आदेश VII, नियम 11 के तहत एक

वादपत्र को खारिज करने के लिए, न्यायालय को प्रारंभिक चरण में ही वादपत्र की सामग्री का अध्ययन करना होगा और बाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए किसी भी बचाव की सहायता के बिना, अपना दृष्टिकोण बनाना होगा। वादपत्र के आधार पर, चाहे वह कार्रवाई के कारण का खुलासा करता हो या नहीं। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, संहिता के प्रावधानों के अनुसार वादपत्र में 20 अगस्त, 1953 के बंधक विलेख का उल्लेख किया गया था और इसकी एक प्रति भी संलग्न थी जिसे वादपत्र के एक भाग के रूप में पढ़ा जाना था। इसके साथ संलग्न बंधक की प्रति में निहित विवरण के साथ वादपत्र पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि 25 जनवरी, 1985 को जब प्रतिवादी ने तत्काल मुकदमा दायर किया था, तब उसके पक्ष में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। नतीजन, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा वादपत्र को सही ढंग से खारिज कर दिया गया।

(10) ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, मैं इस अपील को 3 दिसंबर, 1985 के फैसले को रद्द करने की अनुमति देता हूं, और वाद को खारिज करने वाले विद्वान उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, पानीपत के 3 सितंबर, 1985 के फैसले और डिक्री को बहाल करता हूं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

H.S.B.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा